कटनी नगर निगम का बाबू २० हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

प्लाटकी एनओसी जारी करनेके एवज में मांगे थे २५ हजार रुपये

जबलपुर, (एजेंसी)। नगर निगम में प्लॉट की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए नगर निगम के द्वितीय श्रेणी लिपिक आलोक गर्ग को २० हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। कार्रवाई नगर निगम की संपदा शाखा स्थित कक्ष क्रमांक ४१ में की गई। आरोपी पर आवेदक से एनओसी जारी करने के एवज में २५ हजार रुपये मांगने का आरोप है। बातचीत के बाद वह २० हजार रुपये लेने के लिए तैयार हो गया था।

बैंक से लोन लेने के लिए चाहिए थी एनओसी

लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, आवेदक ६९ वर्षीय अशोक कुमार कनकने निवासी शक्तिनगर, कटनी ने वर्ष २०२५ में नगर निगम से २,००० वर्गफुट का प्लॉट लीज पर लिया था। इस प्लॉट पर गोदाम बनाने के लिए उन्हें बैंक से ऋण की आवश्यकता थी। इसके लिए वह बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचे, जहां बैंक प्रबंधन ने ऋण प्रक्रिया के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लाने को कहा।

इसके बाद आवेदक ने २४ सितंबर २०२६ को नगर निगम में एनओसी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। आरोप है कि नगर निगम में पदस्थ द्वितीय श्रेणी लिपिक आलोक गर्ग ने एनओसी जारी करने के बदले उनसे २५ हजार रुपये की रिश्वत मांगी। बातचीत के दौरान सौदा २० हजार रुपये में तय हुआ। आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की, जिसके बाद टीमने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की।

कक्ष क्रमांक ४१ में बिछाया जाल

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने २३ अक्टूबर को नगर निगम की संपदा शाखा में कार्रवाई की। जैसे ही आरोपी आलोक गर्ग ने आवेदक से २० हजार रुपये प्राप्त किए, टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि बरामद किए जाने की जानकारी दी गई है। आरोपी आलोक गर्ग के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (संशोधित २०१८) की धारा ७, १३(१)(बी) और १३(२) के तहत कार्रवाई की जा रही है।। ट्रैप दल में टीएलओ रेखा प्रजापति, निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक शशि मस्कुले सहित लोकायुक्त जबलपुर इकाई के अन्य सदस्य शामिल रहे।

नगरीय निकायोंमें १,१३४ करोड़की खरीदी की होगी उच्च स्तरीय जांच

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी जरूरतों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल से वर्ष २०२३ से २०२६ के बीच की गई खरीदी में कीमतों का बड़ा अंतर सामने आया है। इस पर राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने स्पष्ट किया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। कांग्रेस ने आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कहीं एलईडी लाइट ३०६ रुपये में खरीदी गई, तो कहीं उसी तरह की लाइट के लिए ११,८०० रुपये चुकाए गए। इसी तरह कचरा वाहनों की खरीद में भी भारी अंतर देखा गया, जहां दो लाख रुपये का वाहन कुछ जगहों पर अतिरिक्त सामान जोड़कर छह लाख रुपये तक का खरीदा गया। करोड़ों की बचत संभव थी: विभागीय कार्यशाला में बताया गया कि यदि ३७४ निकायों द्वारा की गई १,१३४ करोड़ रुपये की कुल खरीदी औसत दरों पर होती, तो लगभग २०० से २५० करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। कड़ी कार्रवाई के निर्देश: नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने स्पष्ट किया है कि प्रसारित वीडियो और तथ्यों के आधार पर उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, कांग्रेस ने इस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।

एसआईआर पर सियासी संग्राम तेज करनेकी तैयारीमें भाजपा

बूथ से लेकर राष्ट्रीय मंच तक चलेगा अभियान

भोपाल, (एजेंसी)। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी राजनीतिक टकराव अब जनसंपर्क और संगठनात्मक अभियान का रूप लेने जा रहा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ भाजपा इस मुद्दे पर अपनी बात जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। पार्टी ने इसके लिए 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र छोड़ो' नारे के साथ २४ अक्टूबर से ५ नवंबर तक अभियान चलाने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश में इस अभियान को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक कर कार्यक्रमों और जिम्मेदारियों का खाका तैयार किया गया है। पार्टी की योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर विधानसभा क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम, पदयात्रा और सोशल मीडिया अभियान चलाने की है। इससे एसआईआर को लेकर चल रही बहस को स्थानीय स्तर तक ले जाने पर जोर रहेगा।

भाजपा की रणनीति केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी नेताओं के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों पर जनता के बीच तथ्य रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा विपक्ष के विरोध को लेकर भी सवाल उठाने की तैयारी में है। पार्टी का तर्क है कि मतदाता सूची से अपात्र नाम हटाना चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जरूरी है। दूसरी ओर, स्क्रूक को लेकर विपक्ष की आपत्तियों और आशंकाओं पर राजनीतिक बहस जारी है।

२४ अक्टूबर से ५ नवंबर तक कार्यक्रम

प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार वार्ता आयोजित करने और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने की योजना है। प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर बुद्धिजीवी सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम किए जाएंगे। अभियान के दौरान आपातकाल और १९८४ के सिख विरोधी दंगों जैसे ऐतिहासिक मुद्दों को भी उठाने की तैयारी है। इसके अलावा पदयात्रा, युवा संवाद, छात्र प्रतियोगिताओं और जनसंपर्क गतिविधियों के जरिए पार्टी अपनी बात विभिन्न वर्गों तक पहुंचाएगी।

नेताओं को सौंपी गई अलग-अलग जिम्मेदारियां

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर तैयार कार्ययोजना में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को अलग-अलग कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे को अभियान का संयोजक बनाया गया है। सांसद एवं प्रदेश महामंत्री लता वानखेड़े, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक, सांसद आलोक शर्मा और विधायक राजेश सोनकर को सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

पदयात्रा से युवा संवाद तक, अलग-अलग टीमें तैयार

कार्ययोजना के अनुसार, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत और वैभव पवार को पदयात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्र चिंतन संवाद के लिए मंत्री राकेश सिंह, विधायक गौरव पारधी और विधायक रीति पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा संवाद की कमान मंत्री इंदर सिंह परमार, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्याम टेलर और मुदित शेजवार को दी गई है। छात्र प्रतियोगिताओं के लिए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, युवा आयोग अध्यक्ष प्रवीण शर्मा और विधायक नीरज ठाकुर की जिम्मेदारी तय की गई है। वहीं, इन्फ्लुएंसर्स आउटरीच कार्यक्रम के लिए उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक अर्चना चिटनिस और मनोरंजन मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मीडिया और सोशल मीडिया पर भी रहेगा जोर

अभियान में मीडिया प्रबंधन और डिजिटल प्रचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और लेखों के प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया, दीपक जैन और आशुतोष तिवारी को दी गई है। सोशल मीडिया अभियान के लिए राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सुयश त्यागी और सुरेंद्र शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, विशेषांक पत्रिकाओं और प्रचार सामग्री के प्रबंधन के लिए भी अलग-अलग पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।

सीईओ जिला पंचायत भिण्ड ने ग्राम पंचायत एण्डोरी सचिव को किया निलंबित

वित्तीय अनियमितता एवं नियमों की अवहेलना और शासकीय धन के गबन करने पर हुई कार्रवाई

भिण्ड, (एजेंसी)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत एण्डोरी सचिव श्री रामवीर चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीईओ जिला पंचायत भिण्ड श्री चौहान ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद का पत्र दिनांक २१ अक्टूबर २०२६ के अनुसार ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद के सचिव श्री रामवीर चौहान द्वारा शासकीय पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये घोर वित्तीय अनियमितता, नियमों की अवहेलना और शासकीय धन का गबन किया गया है। १५वाँ वित्त आयोग की राशि का नियम विपरीत जाकर अवैध उपयोग किया है, तथा सामग्रियों के क्रय में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों तथा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। सचिव के द्वारा बडी राशि २९९४१६८/- का वित्तीय कूटरचित स्वेच्छा चारिता से व्यय किये जाने का उल्लेख किया गया है। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३ तथा म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन, तथा अपील) नियम १९९९ के सुसंगत प्रावधानों के तहत आरोपी सचिव के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अत: ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता एवं नियमों की अवहेलना और शासकीय धन के गबन करने के कारण श्री रामवीर सिंह चौहान सचिव ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, तथा श्री चौहान के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर विभागीय जांच अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद एवं प्रस्तुत कर्ता अधिकारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को नियत किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहद नियत किया जाता है, तथा निलंबन कालमें संबंधितको शासनके नियमानुसार निर्वाह भत्ताकी पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मांगें नहीं मानीं तो ट्रैक्टर-ट्राली लेकर देंगे धरना

मास्टर प्लान-२०४७ के विरोध में टीएनसीपी दफ्तर पहुंचकर किसानों ने सौंपी आपत्तियां, दी चेतावनी

भोपाल, (एजेंसी)। भोपाल मास्टर प्लान-२०४७ के ड्राफ्ट के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान शाहपुरा स्थित टीएनसीपी दफ्तर पहुंचे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले पहुंचे किसानों ने उपसंचालक हरिओम महेश्वरी को आपत्तियां सौंपीं। किसानों ने कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव, बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में निर्माण और सरपंचों को बैठकों में नहीं बुलाने पर सवाल उठाए।

जनपद पंचायत अध्यक्ष फंदा प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं और वे मास्टर प्लान के खिलाफ हैं। सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम पाटीदार ने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान में शामिल सरपंचों को किसी बैठक में नहीं बुलाया गया। किसान गीता प्रसाद पाटीदार ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर आएंगे और टीएनसीपी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान किसान 'किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी' लिखे बोर्ड लेकर पहुंचे। पुलिस-प्रशासन भी सक्रिय रहा।

कृषि भूमि और कैचमेंट एरिया के प्रावधानों पर किसानों की आपत्ति

किसानों की मांग है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने से पहले उनकी समस्याओं और अधिकारों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

बैलेंसिंग राककी अनदेखी पर प्रशासन सख्त, जल्द होगी काररवाई

कलेक्टर ने दिया आश्वासन, स्थल निरीक्षण कर संबंधित विभागों से मांगी जाएगी रिपोर्ट

जबलपुर, (एजेंसी)। विश्वप्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहर बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इस ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के स्थल की कथित उपेक्षा तथा उसके आसपास निर्माण कार्यों को लेकर जनसंगठनों ने प्रशासन के समक्ष चिंता जताई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आश्वासन दिया है कि बैलेंसिंग रॉक का स्थल निरीक्षण कराया जाएगा, संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनसंगठनों ने कलेक्टर को अवगत कराया कि नगर निगम और पर्यटन निगम द्वारा बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। उनका कहना है कि इस प्राकृतिक संरचना से लगभग २० फीट की दूरी पर निर्माण कार्य कराया गया है, जिससे भविष्य में बैलेंसिंग रॉक को नुकसान पहुंचने की आशंका है। संगठनों ने इस मामले में संबंधित विभागों की भूमिका की जांच कर धरोहर के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट का इंतजार

गोरखपुर एसडीएम अनुराग सिंह ने बैलेंसिंग रॉक के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में स्थल की वर्तमान स्थिति, आसपास हुए निर्माण कार्यों और संभावित प्रभावों को लेकर विभागीय रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जनसंगठनों ने प्रशासन से सभी संबंधित विभागों की रिपोर्ट प्राप्त कर मामले में स्पष्ट निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है।

संरक्षण को लेकर उठे सवाल

जबलपुर की पहचान से जुड़े इस अनूठे प्राकृतिक स्थल के संरक्षण को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। जनसंगठनों की मांग है कि बैलेंसिंग रॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थल का तकनीकी निरीक्षण कराया जाए और भविष्य में किसी भी संभावित नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इस संबंध में हुई चर्चा में डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव, सुभाष चंद्रा, सुशीला कनौजिया, संतोष श्रीवास्तव, अशोक यादव, यशवंत कोष्टा, घनश्याम सोनकर और राम मिलन शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

दबंगई दिखाने के लिए की मारपीट, ६ घायल

जबलपुर, (एजेंसी)। कोतवाली और गौरीघाट में मारपीट की दो वारदातें आई हैं कोतवाली में एकता चौक चौपाटी के पास और गौरीघाट रेतनाका चौराहा में बिना वजह गालीगलौज कर बदमाशों ने ६ युवकों के साथ गालीगलौज व मारपीट कर चाकू से हमला कर घायल कर दिया

कोतवाली पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार ४० वर्षीय किसान अभिनव गौतम गत रात लगभग १०.३० बजे अपने मामा के लड़के सचिन तिवारी एवं निक्की तिवारी के साथ एकता चौक चौपाटी के पास गुटखा ले रहा था, तभी कार में हिमांशु मिश्रा अपने साथी प्रथम लोधी, सलिल पटेल के साथ तथा दूसरी स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमपी २० सीएल ४५८७ में श्रेष्ठ रैकवार चौपाटी आया और चारों मिलकर उन तीनों को गालियां देने लगे, मना करने पर चारों ने मारपीट कर दी और श्रेष्ठ रैकवार एवं सलिल पटेल ने चाकू से सचिन तिवारी के सिर तथा निक्की तिवारी के दाहिने पैर के पंजे, गाल में चोटे पहुँचा दी। उसके साथी उदय सुहाने ने निक्की तिवारी व सचिन तिवारी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा ११५(२), ११८(१), २९६(बी), ३५१(३), ३(५) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

इसी प्रकार गौरीघाट में नर्मदा जी के दर्शन कर श्रीनाथ की तलैया पानी की टंकी के पास लाडगंज निवासी २८ वर्षीय सिद्धार्थ श्रीवास्तव अपने दोस्त कनिष्क कुशवाहा, साहिल विश्वकर्मा और निसिका चाचेरकर के साथ घर आ रहा था तभी रास्ते में रेतनाका चौराहा में पान की दुकान के सामने पानी की बोतल लेने रुके तभी पीछे से दो एक्सिस में अज्ञात लड़के आए और बिना किसी बात के उसे गालियां देने लगे मना करने पर एक लड़के ने चाकू से हमलाकर घायल कर दिया उसके साथी कनिष्क व साहल बीच बचाव करने लगे तो इनके साथ भी मारपीट कर चोटे पहुंचा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा ११५(२), ११८(१), २९६(ए), ३५१(३),३(५) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

भाजपा विधायकका अपनी ही सरकारपर तंज

इंडस्ट्रियल कारिडोर को लेकर उठाए सवाल, कहा- छोटे नेताओं से भी कर लेते चर्चा

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर की पाटन विधानसभा सीट से भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरे में लिया है। जबलपुर में बनने वाले नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को लेकर नाराजगी जताई गई है। अजय विश्नोई ने अपने पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए लिखा है कि यदि यह योजना बनते समय सरकार या संबंधित विभाग उनके जैसे छोटे नेताओं से भी चर्चा कर लेता, तो शायद स्थिति कुछ और होती। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उन्हें इस बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी प्रशासनिक बैठकों या किसी आधिकारिक फाइल से नहीं, बल्कि अखबारों में छपने वाली फोटो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उद्योगपतियों की प्रसन्न मुद्रा वाली तस्वीरों से मिल रही है। विधायक का कहना है कि उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा भी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह तक नहीं पता है कि उनकी विधानसभा में आखिर कौन सा उद्योग आ रहा है और उसका धरातल से क्या लेना-देना है।

अब तक उद्योगों के आने का इंतजार

पूर्व मंत्री ने आगे लिखा कि पहले हुई इन्वेस्टर मीट से लेकर अब तक जितने भी आयोजन हुए हैं, उन्हें लगातार इस बात का इंतजार है कि आखिर धरातल पर उद्योग कब और कैसे उतर रहे हैं। उनका यह बयान एक बार फिर पार्टी के भीतर संवाद की कमी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। फिलहाल, सोशल मीडिया पर अजय विश्नोई का यह पोस्ट राजनीतिक हलचल तेज कर गया है और विपक्षी दलों के साथ-साथ राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हो रहा है।

तहसील चौक में आंबेडकर प्रतिमा स्थल की ग्रिल टूटी, गेट गायब

पूर्व पार्षद ने बेलबाग थाने में की शिकायत, प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग

जबलपुर, (एजेंसी)। तहसील चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के गेट और ग्रिल के क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं पूर्व पार्षद शरण चौधरी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। प्रतिमा स्थल की बदहाल स्थिति को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई।

शरण चौधरी के मुताबिक, प्रतिमा स्थल पर लगी लोहे की ग्रिल तोड़ दी गई है, जबकि गेट भी क्षतिग्रस्त होकर गायब है। उन्होंने आशंका जताई कि गेट और ग्रिल को नुकसान पहुंचाने के बाद चोरी की गई है। मामले को लेकर उन्होंने बेलबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन को पत्र देकर प्रतिमा स्थल की मरम्मत कराने तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

स्मारकों की सुरक्षा पर उठाए सवाल

घटना के बाद महापुरुषों की प्रतिमाओं और सार्वजनिक स्मारकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व पार्षद ने आशंका जताई कि इस घटना में असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर गेट और ग्रिल को नुकसान पहुंचाने तथा चोरी करने वालों की पहचान करने की मांग की है।

मरम्मत और निगरानी की मांग

बहुजन समाज पार्टी ने घटना पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से प्रतिमा स्थल की तत्काल मरम्मत कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

मुरैनामें दर्दनाक हादसेके बीच वाहन चेकिंगके नामपर अवैध वसूलीके लगे आरोप

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसे रोकने की उचित कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसी बीच वाहन चैकिंग में लगे आरक्षक की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसने एक बार फिर वाहन चैकिंग और अवैध वसूली को चर्चा में ला दिया है। जानकारी अनुसार नेशनल हाईवे-४४ पर छौंदा टोल प्लाजा के पास सिविल लाइन थाने के आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी वाहन चेकिंग कर रहे थे।

इस दौरान एक तेज रफ्तार मिनी लोडिंग (पिकअप) ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल आरक्षक ने ग्वालियर के बिरला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी ड्राइवर और वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया है। शहीद आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी सेना में १७ साल सेवा देने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे।

मुरैना के बॉर्डरों और आरटीओ चेकपोस्टों पर वाहन चालकों द्वारा जबरन अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में चेकिंग के दौरान नगर निगम सभापति की हूटर कार पर चालान काटने और महापौर की कार को बिना कार्रवाई के जाने देने का मामला भी सामने आया था, जिससे चेकिंग के नियमों पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला सिर्फ मुरैना से जुड़ा नहीं है, बल्कि अधिकांश वाहन चैंकिंग पर अवैध वसूली और आमजन को अनावश्यक परेशान करने के आरोप लगते ही रहते हैं। वाहन चैकिंग के दौरान आम और खास लोगों के लिए अलग-अलग नियमों के आरोप भी लगे हैं, जिस पर चर्चा भी की जाती है, लेकिन व्यवस्था सुधार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं।

अधारताल और गोहलपुर में तलवार चली, ४ घायल

जबलपुर, (एजेंसी)। अधारताल और गोहलपुर थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए रुपए नहीं मिलने की बात पर बदमाशों ने चार युवकों के साथ गालीगलौज व मारपीट कर तलवार से हमला कर दिया घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधारताल पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार जयप्रकाश नगर अधारताल निवासी २७ वर्षीय रजित बघेल आनलाईन सेलिंग का काम करता है गत शाम लगभग ४.३० बजे वह अपने साथी आकाश, सतिओम अपने आफिस से अपने रूम पैदल जा रहे थे तभी सफेद रंग की सुजुकी एक्सिस क्रमांक एमपी २० यू ए ५६४५ में तीन लड़के शराब के नशे में आये और उनके सामने गाड़ी रोककर शराब पीने के लिये पैसों की मांग करने लगे, मना करने पर मंथन केवट एवं मंथन के साथी गाली गलौज व मारपीट करने लगे रंजित ने अपने दोस्त राकेश काजले को फोन पर घटना की जानकारी थी तो वह और यश घटनास्थल पहुँचे तब तक मारपीट करने वाले तीनों भाग गये थे। आकाश एवं सतिओम को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाने वाले थे तभी मंथन केवट एवं मंथन केवट के साथी पुन: तलवार लेकर आए और मारपीट कर तलवार से हमला कर भाग गये। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पर धारा ११५(२), २९६, ११८(१),११९(१), ३५१(२), ३(५) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार गोहलपुर में अजीजगंज पसियाना निवासी २७ वर्षीय मोह.मोहसिन खान गत रात लगभग २ बजे दमोहनाका से डियूटी कर अपने घर जा रहा था रद्दी चौकी पंचशील स्कूल के पास जुबेर बादशाह, समीर करिया, समीर माडल मिले, जहां पर जुबेर बादशाह जेल से छूटकर आया है पैसे नहीं है। खर्च के

मझौली हादसे में सहायक अभियंता निलंबित

काली विसर्जन में करंट का मामला, विभागीय जांच के आदेश

जबलपुर, (एजेंसी)। मझौली में प्रतिमा विसर्जन के दौरान करंट लगने से दो युवकों की मौत और छह लोगों के झुलसने के मामले में बिजली विभाग ने कार्रवाई की है। सहायक अभियंता एमपी प्रजापति को प्रारंभिक रूप से दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है।

हादसे की विस्तृत जांच कार्यपालन अभियंता, सिहोरा को सौंपी गई है। जांच में हादसे के कारणों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

लोहे के पाइप से ११ केवी लाइन उठाने की कोशिश

अधीक्षण यंत्री, जबलपुर ग्रामीण खुशियाल शिववंशी के अनुसार, विसर्जन के लिए ले जाई जा रही प्रतिमा करीब २० फीट ऊंची थी। रास्ते में ११ केवी बिजली लाइन आने के कारण उसे पार कराने के लिए तार ऊपर उठाने का प्रयास किया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक, समिति के कुछ लोगों ने इसके लिए लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया। पाइप के बिजली लाइन के संपर्क में आने से करंट फैल गया और इसकी चपेट में आकर आठ लोग प्रभावित हुए। इनमें तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य झुलस गए।

मौके पर मौजूद था लाइन स्टाफ

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान मौके पर लाइन स्टाफ मौजूद था। उनका दावा है कि समिति के लोगों को तार ऊपर उठाने के लिए कर्मचारियों की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने स्वयं लोहे के पाइप से लाइन उठाने का प्रयास किया। इसी दौरान हादसा हो गया।

जांच में तय होगी विभागीय लापरवाही

हादसे के बाद सहायक अभियंता एमपी प्रजापति को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, विभागीय जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं की जांच अभी बाकी है। जांच अधिकारी यह पता लगाएंगे कि मौके पर बिजली कर्मचारियों की क्या भूमिका थी, बिजली लाइन के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे या नहीं और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन हुआ था या नहीं। कार्यपालन अभियंता, सिहोरा को सौंपी गई जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एयरपोर्ट रोड पर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा

ब्रिज से गुजर रहा ट्राला साइड वाल तोड़ २० फिट नीचे गिरा बाडी ब्रिज पर ही अटकी रही, चेचिस सर्विस लेन पर जा गिरा

भोपाल, (एजेंसी)। राजधानी भोपाल के गांधीनगर इलाके में स्थित एयरपोर्ट रोड पर शुक्रवार को दिल दहला वाला हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के सामने बने ब्रिज से गुजर रहा तेज रफ्तार ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर ब्रिज कि सीमेंट की साइड वॉल से टकराया और वॉल को तोड़ता हुआ करीब २० फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था, कि भारी भरकम ट्राले का तो चेचिस नीचे गिर गया, लेकिन उसकी बॉडी ब्रिज के ऊपर ही अटक गई। भीषण दुर्घटना में ट्राला चालक को गंभीर चोटें आई हैं, उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ उसका इलाज जारी है। हादसा शुक्रवार सुबह करीब ७:३० बजे उस समय हुआ जब ट्राला बायपास की और जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ब्रिज से उतरते समय ट्राला की रफ्तार तेज थी, अचानक ही चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बेकाबू ट्राला सीधे ब्रिज पर बनी सीमेंट से बनी साइड वॉल से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार टूट गई और ट्राले का निचला हिस्सा करीब २० फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा। भीषण एक्सीडेंट को देख लोग सन्न रह गए, नीचे गिरो ट्राले का चेचिस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि उसकी बॉडी ब्रिज पर ही अटकी रही। हादसे की सूचना मिलने पर पहुचीं पुलिस द्वारा घायल चालक को अस्पताल पहुचायां गया। बतायसा गया है की जिस समय ट्राला नीचे गिरा, उस दौरान सर्विस लेन से कोई अन्य वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था। जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई। यदि उस समय सर्विस लेन पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद होता, तो हादसा जानलेवा भी हो सकता था। गांधीनगर थाना पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट रोड पर हुए हादसे की जांच की जा रही है, दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और ट्राला अनियंत्रित कैसे हुआ इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

मुंबई में ११७ साल पुरानी एडवर्ड विला बेचेगी सरकार!

हेरिटेज बिल्डिंग की कीमत सैकड़ों करोड़ होने का अनुमान

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश सरकार अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मुंबई में स्थित अपनी ११७ साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत एडवर्ड विला से कमाई करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस संपत्ति के व्यावसायिक इस्तेमाल और इसके पट्टे के बचे हुए अधिकारों को बेचने या हस्तांतरित करने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। इसके लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शु